

न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- आर.के. जायसवाल, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :- 29/2019

(RCMS No. :-2019/00072)

उनवानी प्रकरण :-

1. राजभान पुत्र रामचरन जाति गुर्जर निवासी ग्राम कहारपुरा तहसील बसेड़ी
जिला धौलपुर—अपीलान्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बसेड़ी—रेस्पोडेण्ट।

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.7.2019

तहसीलदार बसेड़ी प्र.सं. 12/19 उनवानी

राज0 सरकार बनाम राजभान अंतर्गत

धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. अपीलान्ट की ओर से :- श्री राजेन्द्र सिंह राना अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :- श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :-15.11.2019

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बसेड़ी के निर्णय दिनांक 22.07.2019 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए अर्थदण्ड एवं सजा का आदेश पारित किया है। अपीलाधीन आदेश विधि विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की कोई तामील व्यक्तिगत रूप से नहीं हुई, अपीलान्ट के सम्मन की तामील परिवार के सदस्य पर होना बताकर एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर अपीलान्ट को दोषी ठहराये जाने में कानूनी भूल की है। अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर कमी कोई अतिक्रमण नहीं किया है और ना भविष्य में सरकारी जगह पर कोई अतिक्रमण करेगा, अपीलान्ट इस आशय का शपथ पत्र पेश कर देगा। अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम 20.8.2019 की सम्बन्धित पटवारी के माध्यम से हुई है। जानकारी दिनांक से अपील अपीलान्ट

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर



अन्दर म्याद प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.7.2019 निरस्त किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.7.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

म्याद के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर विधिवत नहीं हुई है। अपीलान्ट की बैंक पर निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पटवारी हल्का से दिनांक 20.8.2019 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। रेस्पोंडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील विधिवत रूप से कराई गई है। अपीलान्ट बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नहीं हुआ है। अपील अपीलान्ट म्याद बाहर पेश की गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद मानी जाती है।

उभय पक्ष की अन्तिम बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए लगान की 50 गुना शास्ती राशि 30/- एवं 15 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर विधिवत नहीं हुई है, और ना ही साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक पक्षीय है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं जिससे अपीलान्ट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना जा सके। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 20.8.2019 को हुई। अपील प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही व देरी नहीं की है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में कोई कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.7.2019 खारिज किया जावे।

(आरो के जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर



रैस्पोंडेंट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्त विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की अपीलान्त पर विधिवत तामील हुई है। अपीलान्त बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.7.2019 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान से यह स्पष्ट है कि अपीलान्त विवादित भूमि पर पूर्ववर्ती अतिक्रमी है। किन्तु अपीलान्त द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि अपीलान्त ने विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दिया है। तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्त को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार बसेड़ी मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्त ने कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। यदि अपीलान्त शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तहसीलदार अपीलान्त के विरुद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं असल शपथ पत्र निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाए जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(~~रविशंकर कुमार~~ जायसवाल)
जिला कलेक्टर, घाज़िपुर
जिला कलेक्टर, घाज़िपुर